SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, I think, what the hon. Member is alluding to is the military service pay which right now is Rs. 1000/- and, as you know-- while the officers get Rs. 6000/- —this anomaly has been pointed out after the recommendations and this is being examined.

SHRI SYED AZEEZ PASHA: What about de-linking it from the Central Government employees' pay?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: That is another issue which is being raised not only by the men from Armed Forces Forces but also by a lot of hon. MPs and that also will be looked into.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब उनको परमानेंट किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, उनकी एसीआर में देखी जाती है और साथ में उनकी च्वाइस भी पूछी जाती है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि जिन लोगों को शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब उनको परमानेंट किया जाता है, तब उनका रैंक लो कर दिया जाता है? अगर वह मेजर है तो उसको कैप्टन बना दिया जाता है, अगर वह कर्नल है तो उसको मेजर बना दिया जाता है? क्या इस वजह से भी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोग हैं, वे परमानेंट कमीशन में ऑप्ट नहीं करते हैं, यह मैं जानना चाहती हूं?

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, after the recommendations of the A.V. Singh Committee Report what has been done is, the number of years needed for promotion for the three categories of Captain, Major and Lieutenant Colonel have been shortened to the duration of two years, six years and 13 years which has certainly helped the cause.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: No, no, my point is, when the short service commissioned officers were made permanent, their rank was always made lower. If he is in the rank of Major, when he is made a permanent officer he is given the rank of Captain. Is it true and that is why so many officers are opting out of getting permanent commission. That was what I wanted to know.

SHRI M.M. PALLAM RAJU: Sir, I do not think that would be true because, I think, once they are inducted into the Armed Services, as they rise in the ranks, both the short service commissioned officers and permanent service commissioned officers are treated alike and their promotional aspects are also treated on par.

रुपये के मूल्य में हो रही वृद्धि के कारण लघु उद्योगों में उत्पन्न बेरोज़गारी

*422. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:**††
डा॰ मुरली मनोहर जोशी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में हो रही वृद्धि और लघु उद्योग क्षेत्र में बंद पड़ी 4 लाख इकाइयों के कारण वर्ष 2007 के दौरान 13 लाख कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राजमोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष 3 अप्रैल, 2007 तथा 16 जनवरी, 2008 के मध्य अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुपए के मूल्य में हुई वृद्धि के प्रभाव को निर्यातक समुदाय विशेष रूप से उन क्षेत्रों द्वारा तीव्रता से महसूस किया गया जो श्रम सघन हैं, जिनकी निविष्टियां कम आयात आधारित हैं, तथा जहां मूल्य वृद्धि निम्न है रोजगार, उत्पादन में कमी तथा परिणामतः निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निर्यात में अत्यधिक गिरावट एक वास्तविकता बन गई है। रुपए में मूल्य में वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया।

समिति के निष्कर्षों के ब्यौरे विवरण I तथा II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विकासशील देशों के अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर आई एस) अध्ययन के आधार पर रोजगार अनुमान

	निर्यात (अमरीकी डालर बिलियन)	कुल रोजगार (संख्या लाख में)	वर्धमान रोजगार (संख्या लाख में)
2003-04	63.84	144.28	–
2004-05	83.54	188.80	44.52
2005-06	103.09	232.99	44.18
2006-07	124.63	281.67	48.68
2007-08	160.00	361.61	79.94

आर आई एस अध्ययन के अनुसार 1 बिलियन अमरीकी डालर निर्यात से 2.26 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 दौरान निर्यात की आकलित वार्षिक वृद्धि

वर्ष 2007-08 के दौरान निर्यात की आकलित वार्षिक वृद्धि	कालम (1) में विकास दरों के तदनुरूपी निर्यात (बिलियन अमरीकी डालर)	कुल रोजगार (संख्या लाख में)	वर्धमान रोजगार (संख्या लाख में)	वर्ष 2006-07 में वर्धमान रोजगार के स्तर से भिन्नता
1.28*	160*	361.61	79.94	31.26
1.20	150.0	339.00	57.34	8.66
1.18	147.5	333.35	51.69	3.01
1.16	145.0	327.70	46.04	-2.64
1.14	142.5	322.05	40.39	-8.29
1.12	140.0	316.40	34.74	-13.94
1.10	137.5	310.75	29.09	-19.59

*वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य

विवरण-I दर्शाता है कि वर्ष 2006-07 में 125 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात स्तर पर निर्यात क्षेत्र में कुल रोजगार (प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष) 282 लाख था जिनमें से 49 लाख रोजगार निर्यात वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान सृजित वर्धमान रोजगार थे। तथापि, यदि निर्यात वृद्धि घटकर 16 प्रतिशत या उससे कम हो जाए, तो वर्धमान रोजगारों में वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में कमी होने की संभावना है।

Loss of jobs in SSI Units due to appreciation in Rupee value

†*422. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to appreciation in value of Indian Rupee against dollar and 4 lakh units being closed in small industry sector, 13 lakh workers are likely to be rendered jobless during 2007; and

(b) if not, the assessment of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The rupee appreciated by 9.8 per cent against the US dollar during the last financial year between April 3, 2007, and January 16, 2008. The impact of rupee appreciation has been acutely felt by the exporting community, in particular, by those sectors which are labour intensive, whose inputs are less import driven, and where value addition is low. Loss of employment, output and consequently steep reduction in exports against the target set has become a reality. In order to assess the impact of the rupee appreciation, a Committee was set up under the Ministry of Commerce and Industry.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha

Details of the findings of the Committee are given below in Statement I & II.

Statement-I

Estimates of Employment based on Research & Information System for developing countries (RIS) study

	Exports (US $ Billion)	Total Employment (lakh Nos.)	Incremental Employment (lakh Nos.)
2003-04	63.84	144.28	—
2004-05	83.54	188.80	44.52
2005-06	103.09	232.99	44.18
2006-07	124.63	281.67	48.68
2007-08	160.00	361.61	79.94

According to RIS study, US $ 1 billion of exports is estimated to generate 2.26 lakh jobs.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

Statement-II

Projected Annual Growth of Exports during 2007-08

Projected Annual Growth (%) of exports during 2007-08	Exports (US $ Billion) corresponding to growth rates in Col. (1)	Total Employment (lakh Nos.)	Incremental Employment (lakh Nos.)	Difference from level of incremental employment in 2006-07
1.28*	160*	361.61	79.94	31.26
1.20	150.0	339.00	57.34	8.66
1.18	147.5	333.35	51.69	3.01
1.16	145.0	327.70	46.04	-2.64
1.14	142.5	322.05	40.39	-8.29
1.12	140.0	316.40	34.74	-13.94
1.10	137.5	310.75	29.09	-19.59

*Target set for 2007-08

Statement-I shows that at a level of exports valued at US $ 125 billion in 2006-07, the total employment (direct + indirect) in the export sector was 282 lakh of which 49 lakh jobs were incremental jobs created during the year as a result of export growth. However, the incremental jobs are expected to be lower in 2007-08 compared with 2006-07 if export growth slips to 16 per cent or less.

श्री राव मोहिन्दर सिंह मजीठा: चेयरमैन साहब, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं इनफॉर्मेशन चाहता हूं कि पिछले सालों से डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसके कारण भारत में अनेक उद्योग प्रभावित हुए हैं और उद्योगों से रिलेटिड मिनिस्ट्रीज ने कोशिश की है कि सरकार की तरफ से उनको रियायत दी जाए। मैं कहना चाहता हूं कि देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा नौजवानों को रोजगार देती है। आज जब रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, तो ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूं कि लेबर मिनिस्ट्री के क्या कुछ ऐसे प्रपोजल्स सरकार के सामने रखे हैं जिनसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, वे रुक जाएं?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न ज्यादातर कॉमर्स मिनिस्टरी से संबंधित है जिसके मंत्री मेरे कुलीग जयराम रमेश जी हैं। फिर भी देश में स्थिति ऐसी है कि एक तरफ से dollar appreciation की वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। 22.9 परसेंट ग्रोथ रेट भी है। इसकी वजह से कुछ बैलेंसिंग हो रही है। फिर कार्मिक लोगों के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। जब रिडक्शन हो रहा है। there is increase in exports also. मार्किट अमेरिका से थोड़ी शिफ्ट होकर यूरोप और अफ्रीका की तरह हो रही है। इसके बारे में अगर और प्रश्न पूछेंगे तो my colleague is ready to answer it. Shri Jairam Ramesh is very much here.

MR. CHAIRMAN: Not at this time.

SHRI OSCAR FERNANDES: I have dealt wtih the labour question. This question pointedly relates to exports. It would have been better if they had sent the question to the Ministry of Commerce.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: आपके माध्यम से मेरा सप्लीमेंटरी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं तो फिर बेरोजगारी की समस्या और भंयकर रूप लेती जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी को यही रोकने के लिए क्या सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों की पहचान की है, जहां देश में सबसे अधिक तादाद में पाए जाने वाले अन-स्किल्ड और स्किल्ड को रोजगार मिल सके?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: सर, हमारी ज्यादातर इंफार्मेशन है कि तमिलनाडु में इसका प्रभाव हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी इसका प्रभाव हुआ है। जैसा हमने बताया कि एक तरफ से अमेरिका से एक्सपोर्ट का रिडक्शन हो रहा है और वहीं मार्केट अभी यूरोप की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। ग्रोथ रेट बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से एक्सपोर्ट घट रहा है, फिर एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ रहा है यूरोप की तरफ से तथा और आल्टरनेट भी है। तमिलनाडु में श्रमिकों की संख्या जरूर है। फिर एक कॉर्मिक को 5-6 दिन का काम है, तो अभी रिडक्शन होकर 5 दिन से 4 दिन का काम मिल रहा है। हमारी एक योजना एस०आई० कारपोरेशन की है। जब उनका अनएम्प्लोयमेंट होता है तो हमारे पास राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से हम परमानेंट एम्प्लोई को 6 महीने का एलाउंस दे रहे हैं। जिन्होंने पांच साल तक प्रीमियम दिया है, उनको कंपंसेशन भी मिल रहा है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, आज फिर वही एक दूसरा नमूना है, कल तो हमने देखा ही था कि जिसमें सवाल कुछ है और जवाब कुछ है। और हालत यह है कि दो मंत्री अगल-बगल बैठे हैं, वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। कॉमर्स मिनिस्टर मदद नहीं कर रहे हैं, वे मदद मांग रहे हैं और वे मदद नहीं दे रहे हैं। आम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इन गरीब बेरोजगारों की मदद कहां से करेंगे।.... **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

डा० मुरली मनोहर जोशी: सर, हम हालत देख रहे हैं, वे मदद मांग रहे हैं उनसे और वे मदद नहीं दे रहे हैं। यही सरकार की हालत है, सरकार की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है। वह सवाल उधर ट्रांसफर कर सकते थे, उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। अब आप देखिए कि यह हालत है। पहले तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवाल कुछ है और जवाब कुछ है। यह आप गौर करते हैं और आपके सामने सवाल और जवाब दोनों आ जाते हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है कि सवाल कुछ किया जा रहा है और हर मंत्री जवाब कुछ दे रहा है। या तो सरकार ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: डा० साहब, आप सवाल तो पूछिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मेरा सवाल तो यही है कि शुरूआत में क्या पुछूं, साहब, जब जवाब ही कुछ और है। लेकिन फिर भी मैं इनसे जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट यह है कि हमारे देश में स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज बंद हो रही हैं और चार लाख से ज्यादा स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज इस बीच में बंद हुई हैं और उनके अंदर 13 लाख वर्कर्स की जॉब खत्म हुई है। यह ठीक है कि कुछ उसमें एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड भी थीं, लेकिन ऐसी भी हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड नहीं हैं। हम आपसे यह जानना चाहते थे कि अगर यह बात सच है तो अन-एम्प्लोयमेंट बढ़ा है और अगर अनएम्प्लोयमेंट बढ़ा है, तो फिर आप इनको एम्प्लोयमेंट दिलाने के लिए क्या कर रहे है? दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल सैक्टर में जहां पहले 67 परसेंट एम्प्लोयमेंट होता था, वह घटकर अब 52 परसेंट रह गया है। वह तो सीधे-सीधे आपके महकमें के अंदर है। इसलिए इस रिडक्शन के बारे में आप क्या कर रहे हैं? कुल मिलाकर के जो आज देश में बेरोजगारी की स्थिति है, वह बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब वह बात अलग है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री अपने आंकड़े देकर यह साबित करना चाहती है कि इतना बढ़ेगा, वह सब एस्टीमेटेड आंकड़े हैं। उसमें असलियत कितनी होगी, वह हम खुद जानते हैं कि उसका दो साल, चार साल बाद पता लगेगा। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या आप इस बात पर ध्यान देंगे कि स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज को वे रियायतें मिलें जिससे कि वहां अन-एम्प्लोयमेंट रुक जाए? आज उनको जो रियायतें मिल रही थीं, वे बंद हो गई हैं। आपके बगल में ही कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनसे पूछ तो लें कि वे क्या रियायतें दिलाना चाहते हैं, वह ही बता दें आप हमें। लेकिन कुछ तो बताएं इन बेरोजगारों के हाल पर, भगवान के नाम पर इन बेरोजगारों के लिए कुछ तो कीजिए आप। ...**(व्यवधान)**... राम के नाम पर तो सारी बेरोजगारी मिट जाएगी, पहले इनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: हमने मान लिया कि रूपी वेल्यूएशन का बजट है, अमेरिका से एक्सपोर्ट रिडक्शन हो रहा i इसके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री कुछ सुविधा दे रहा है They are trying to maintain the exports. This i number one.

The second one is, export market is increasing to the Europe and I have given the figure: Sir, there is an increase of 22.9% in exports. यह स्थिति नहीं है, कुछ स्मॉल स्केल यूनिट्स where expert are there क्लोज हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि एग्रीकल्चर लेबर के बारे में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया..... । इसके लिए रूरल एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम हमने लागू कर दी है और एक साल में 100 दिन का गारंटिड एम्प्लोयम हमारे कार्मिक लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

श्री रूद्रनारायण पाणि: यह स्कीम आपके मंत्रालय की नहीं है। ...(व्यवधान)... यह स्कीम ग्रामीण रोजगार मंत्राल की है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: It is a Government scheme.

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: सर, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की जरूर है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा कि एग्रीकल्च वर्कर्स के बारे में आप क्या कर रहे हैं, इसलिए यह रिप्लाई देना पड़ा। गवर्नमेंट को एक ही मंत्री नहीं चलाते हैं, सारे म मिलकर चलाते हैं और रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम भी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए हमने यह रिप्लाई आ सामने दिया है।

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, this is a question related to multiple Ministries. And, i very unfortunate that Mr. Fernandes has to bear the burden of it. But since it has been rais here, I think, it merits an answer. Normally, when the rupee appreciates the Reserve Bank India steps into picture in order to shore up the rupee by buying the dollars from the mark Is it a fact that the Government has directed the Reserve Bank of India not to do this fr March, 2007 with the fear that it would increase the liquidity in the economy and that wo fuel inflation? They have a wrong diagnosis. This is not the reason why this inflatior taking place. The net result is that you have allowed the rupee to appreciate and as a re lakhs of jobs have been lost. This is a fact that has been reported by various studies. Th have been losses of jobs in lakhs in the textile sector, in the leather sector, which are the largest export earners in the country. Whatever illusion we may have that our exports growing for the European Union, that does not compensate for the loss of jobs that taking place. Therefore, what we want to know from the Government is that will they aban the erroneous diagnosis and allow the Reserve Bank of India to operate to shore up Indian rupee so that the people do not lose jobs as a result of this appreciation.

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, this is a question that I cannot anwer straightway.

SHRI SITARAM YECHURY: I know; I know.

SHRI OSCAR FERNANDES: I can lay before you some of the schemes which have b initiated by the concerned Ministries. These are extension of BEPB scheme till 31.5.2(...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: No, Sir, It is not the ...*(Interruptions)*...

SHRI OSCAR FERNANDES: I have already stated that I cannot answer this que straightway. I will request the Finance Minister to give the necessary information tc House.

PROF. P. J. KURIEN: Sir, this is a question which was put to the Labour Minister. But the upplementaries are being directed to the Finance Ministry and The Commerce Ministry. But will stick to the Labour Ministry. The main question is whether we are giving the imporatance ɔ the SSI sector that it requires. For unit investment, the SSI sector can give ten times more mployment than big industries. But it is a hard fact that the SSIs are neglected. This sector ; facing serious crisis due to two main reasons—due to severe competition and due to ppreciation of rupee. Because of these two reasons the SSIs are really facing a crisis. A umber of units are being closed. And, because of their closure a large number of people ave become unemployed. Therefore, I would like to know whether the Labour Ministry has ɔnducted any study as to the number of people who have lost employment due to SSI osures. If 'Yes', what is the number? Secondly, if you have found that people have lost jobs, hat is the package that you have brought to help those people who have become unemployed ıe to our own policy and also due to appreciation of rupee?

SHRI OSCAR FERNANDES: Sir, I will take up first the second part of the question. I have :eady mentioned that we have launched a scheme under the ESI Corporation. It is called the ajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana. If any person, who is contributing to the ESI for a riod of five years, loses the job, he gets a compensation for a period of six months, and by at period, had should be able to get another job.

The other part of the question, again, relates to my colleague in the Ministry of Small ale Industries. I will request him to provide the necessary answer.

SHRI RAHUL BAJAJ: Thank you, Mr. Chairman. Sir, the aim should be to prevent problems d not to cure them after they take place. Unfortunately, this is not the responsibility of my nd, Mr. Oscar Fernandes. But, partly, this question relates to Mr. Jairam Ramesh's Ministry ɔ. So, I want to know from both whether they will use their good offices to persuade the ance Ministry to control this appreciation in the rupee, which has risen from 9 per cent to per cent during 2007. When we have a balance of trade deficit, balance of payment deficit, inflation rate is higher, our interest rate is higher; the rupee should depreciate. The major son for this appreciation is the inflow of FDI money; hot money. I am not against FII. The money is doing this, but, we say, what happened to employment and what happened to orts etc. Sir, Europe and other countries cannot help.

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI RAHUL BAJAJ: Our exports are denominated in dollars, whichever country it might So, please use your good offices. Will you do so, Sir? Will you persuade the Finance istry-to put some restrictions by imposing a token tax or some other charge on FII ıey? ...*(Interruptions)*...

HRI SITARAM YECHURY: Sir, this is a very strange situation. ...*(Interruptions)*... I am ing him to come and join this side. ...*(Interruptions)*...

IR. CHAIRMAN: Mr. Sitaram Yechury, please do not interrupt. ...*(Interruptions)*... Let uestion be answered.

HRI OSCAR FERNANDES: Sir, the hon. Member has made a very good suggestion. I ake up this matter with the other colleagues, and see that they have a meeting, and come vith some solution to this problem.